

उत्तराखण्ड शासन


कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-384 / XXX (2) / 2011

देहरादून: दिनांक 16 मार्च, 2011

अध्याचन संख्या-384 / XXX (2) / 2011 दिनांक 16 मार्च 2011 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग लेखाकार एवं सहायक लेखाकार विनियमावली, 2011 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूडकी, हरिद्वार को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-क में मुद्रित करा कर इसकी 25 प्रतियां कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव

अधिसूचना

राज्यपाल, “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 318 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय में समस्त विद्यमान विनियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग लेखाकार एवं सहायक लेखाकार विनियमावली, 2011

भाग 1

सामान्य

- | | |
|---------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. (1) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग लेखाकार एवं सहायक लेखाकार विनियमावली, 2011 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| सेवा की प्राप्ति | 2. सेवा से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग लेखा संवर्ग अभिप्रेत है, जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित है। |
| परिभाषाएं | 3. जब तक कि विषय या संवर्ग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस विनियमावली में –
(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो “भारत का संविधान” के भाग II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;
(ग) 'आयोग' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
(घ) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;
(ङ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
(च) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
(छ) 'सेवा का सदस्य' से इस विनियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस विनियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है; |

(ज) 'सेवा' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग लेखा संवर्ग अभिप्रेत है;

(झ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई विनियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो; तथा

(ञ) 'भर्ती का वर्ष' से कैलेंडर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग 2

संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।
- (2) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपविनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी है;

परन्तु यह कि—

- (क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा;
- (ख) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

भाग 3

भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:—

- (1) सहायक लेखाकार— आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
- (2) लेखाकार— मौलिक रूप से नियुक्त सहायक लेखाकारों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—
- (क) भारत का नागरिक हो; या
 - (ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए; या
 - (ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो;

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी— जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8. सेवा में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :—

सहायक लेखाकार—

- (क) बी.काम या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकान्टेन्सी तथा कम्प्यूटर संचालन में 'ओ' लेवल का सर्टीफिकेट, जिसमें कम्प्यूटर पर 5000 की-डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति होना आवश्यक है;
- (ख) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान।

- अधिमानी अर्हता** 9. अभ्यर्थी, जिसने—
- (1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो; या
 - (2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
- आयु** 10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए;
- परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।
- चरित्र** 11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।
- टिप्पणी**—संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
- वैवाहिक प्रास्थिति** 12. पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी;
- परन्तु यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।
- शारीरिक योग्यता** 13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं

है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी की वह वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें;

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग 5

भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की
अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उसे दी जायेगी।

सीधी भर्ती की
प्रक्रिया

15. सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया –
- (1) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र मंगायेगा। आवेदन-पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।
 - (2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश-पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
 - (3) सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित पाठ्यक्रम में उल्लिखित विषयों के प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग द्वारा विनियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की योग्यताक्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुत करेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

लेखाकार के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया –

- (1) लेखाकार पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति एक चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

- (क) नियुक्ति प्राधिकारी — अध्यक्ष;
(ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित आयोग का एक वरिष्ठ अधिकारी — सदस्य
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित आयोग का वित्त नियंत्रक — सदस्य;

परन्तु यह कि यदि उपरोक्तानुसार गठित चयन समिति में अध्यक्ष व सदस्य में से कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नहीं है तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति में से किसी एक अधिकारी को, जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो, सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट करेगा।

- (2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयन्नोनति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार पात्रता सूची तैयार करेगा।

स्पष्टीकरण— इस विनियम के उपविनियम (ख) में :—

- (क) रिक्तियों की संख्या से भर्ती के वर्ष के प्रारम्भ के समय विद्यमान या भर्ती के वर्ष के दौरान होने वाली मौलिक या अस्थायी रिक्तियों की कुल संख्या अभिप्रेत है;
(ख) सभी प्रकार की रिक्तियों के लिए केवल एक पात्रता सूची तैयार की जायेगी।
(3) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूची को उनकी चरित्र-पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाये, चयन समिति के समक्ष रखेगा और उसे भिन्न-भिन्न प्रकार की रिक्तियों की संख्या भी सूचित करेगा।
(4) चयन समिति उपविनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।
(5) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग 6

नियुक्ति, परीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

17. (1) उपविनियम (2) के अध्याधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर, जिसमें वे विनियम 14, 15 अथवा 16 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

- (2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा।

परिवीक्षा

18. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक-पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे;
- परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।
- (3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- (4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपविनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

19. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने—
- (क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो ;
- (ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो ;
- (ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;
- (घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है ; तथा
- (ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता

20. (1) मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं;

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

- (2) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उनके पोषक संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

भाग 7

वेतन आदि

वेतनमान

21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
- (2) इस विनियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

22. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी;

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

- (2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा;

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

- (3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य

के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग 8

अन्य प्राविधान

- पक्ष समर्थन** **23.** सेवा या पद के संबंध में लागू विनियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का प्रमाण उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।
- अन्य विषयों का विनियमन** **24.** ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन विनियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।
- सेवा शर्तों का शिथिलीकरण** **25** यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी विनियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस विनियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे;
- परन्तु यह कि जहाँ कोई विनियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहाँ विनियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।
- व्यावृत्ति** **26.** इस विनियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट 'क'

[कृपया विनियम 4 का उपविनियम (2) तथा विनियम 21 का उपविनियम (2) देखें]

क्रम सं०	पद का नाम	वेतनमान (रु०में)	पदों की संख्या		कुल योग
			स्थायी	अस्थायी	
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक लेखाकार	5200-20200 ग्रेड पे 2800	—	02	02
2.	लेखाकार	9300-34800 ग्रेड पे 4200	—	01	01

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of “**the Constitution of India**”, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 384/XXX(2)/2011 Dated 16/3/2011 for general information.

Government of Uttarakhand
Personnel Department-2
No. 384 /XXX(2)/2010
Dehradun:Dated: 16 March, 2011

Notification

In exercise of the powers conferred by the Article 318 of “**the Constitution of India**” and in the superannuation of all existing regulations and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following regulations regulating recruitment and the condition of service of persons appointed to the Uttarakhand Public Service Commission Accountant and Assistant Accountant Service.

THE UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION ACCOUNTANT AND ASSISTANT ACCOUNTANT SERVICE REGULATIONS, 2011

PART-1

General

Short title and commencement	1.	(1) These regulations may be called the Uttarakhand Public Service Commission Accountant and Assistant Accountant Service Regulations, 2011. (2) They shall come in to force at once.
Status of Service	2.	The service of Uttarakhand Public Service Commission Account Cadre is a such State service comprising of Group “C” Posts.
Definitions	3.	In these regulations unless there in anything repugnant in the subjects or context- (a) “ Appointing Authority ” means the Secretary, Uttarakhand Public Service Commission; (b) “ Citizen of India ” means, a person, who is or is deemed to

		<p>be a citizen of India under Part II of “the Constitution of India;”</p> <p>(c) “Commission” means Uttarakhand Public Service Commission;</p> <p>(d) “Constitution” means “the Constitution of India”;</p> <p>(e) “Government” means the State Government of Uttarakhand;</p> <p>(f) “Governor” means the Governor of Uttarakhand;</p> <p>(g) “Member of cadre” means a person substantively appointed under the regulations or the regulation or order in force prior to the commencement of these regulations, to a post in the cadre of the Service;</p> <p>(h) “Service” means Uttarakhand Public Service Commission Account Cadre;</p> <p>(i) “Substantive Appointment” means an appointment not being <i>an adhoc</i> appointment on a post in the cadre of the Service, made after selection in accordance with the regulations and, if there is no regulations, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government; and</p> <p>(j) “Year of recruitment” means a period of twelve months commencing from the First day of July of a calendar year.</p>
		<p style="text-align: center;">PART-II</p> <p style="text-align: center;"><u>Cadre</u></p>
Cadre of Service	4.	<p>(1) The strength of the service and of each category of number of posts shall be such as may be determined by the Government from time to time.</p> <p>(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-regulation (1), be as given at annexure "A";</p>

		<p>Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India;</p> <p>Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government;</p> <p>Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a Certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Bureau of Uttarakhand.</p> <p>NOTE- A candidate in whose case a Certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused may be admitted to an Examination or Interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary Certificate being obtain by him or issued in his favour.</p>
Education Qualifications	8.	<p>A candidate for recruitment to the various posts in the service must posses the following qualifications :-</p> <p>Assistant Accountant –</p> <p>(a) B.com or Post Graduate Diploma in Accountancy and ‘O’ level certification of operation on computer, 5000 Key-depression per hour speed on computer be must;</p> <p>(b) knowledge of Hindi in Devnagiri Script.</p>
Preferential Qualifications	9.	<p>A candidate, who has -</p> <p>(a) served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or</p> <p>(b) obtained a 'B' Certificate of National Cadet Corps shall other thing being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.</p>
Age	10.	<p>A candidate for direct recruitment must have attained the</p>

		<p>Provided that –</p> <p>(a) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without there by entitling any person to compensation; or</p> <p>(b) the Governor may create such additional permanent or temporary post, as he may consider proper.</p>
		<p>PART-III</p> <p><u>Recruitment</u></p>
Source of Recruitment	5.	<p>Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made from the following sources :–</p> <p>(a) Assistant Accountant— by direct recruitment through Commission;</p> <p>(b) Accountant—by promotion through Departmental Selection Committee amongst from such substantively appointed Assistant Accountants, who have completed 05 years service as such on the first day of the year of recruitment on passed departmental examination.</p>
Reservation	6.	<p>Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories of the State of Uttarakhand shall be in accordance with orders of the Government in force at the time of recruitment.</p>
		<p>PART-IV</p> <p><u>Qualification</u></p>
Nationality	7.	<p>A candidates for direct recruitment to a post in the Service must be;</p> <p>(a) a citizen of India;</p> <p>(b) a Tibetan refugee who came over to India before January 01, 1962 with the intention of permanently settling in India; or</p> <p>(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka ,or any of the East African countries of</p>

		<p>minimum age of Twenty-one years must not have attained the age of more than Thirty-Five years on January 1 of the year in which recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period January 1 to June 30 and on July 1 if the posts are advertised during the period July 1 to December 31;</p> <p>Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories to the State of Uttarakhand, as may be notified by the Government from time to time, shall be grater by such number of years as may be specified.</p>
Character	11.	<p>The character of a candidate for direct recruitment to a post in Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall, satisfy itself on this point.</p> <p>NOTE- Person dismissed by the Union Government or any state Government or by Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Person convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.</p>
Marital Status	12.	<p>A male candidate, who has more than one wife living or a female candidate, who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service;</p> <p>Provided that the Government may, If satisfied that there exist special reason for doing so, exempt any person from the operation of the regulation.</p>
Physical Fitness	13.	<p>No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his</p>

		<p>duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the regulations framed under fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand Book Volume II Part III;</p> <p>Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.</p>
		<p style="text-align: center;">PART-V</p> <p style="text-align: center;"><u>Procedure for Recruitment</u></p>
Determination of vacancies	14.	<p>The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment, as also the number of vacancies to be reserved for the candidate belonging to the Scheduled Castes, Schedule Tribe and other categories to the State of Uttarakhand, under regulation 6 and shall intimate the information to the Commission.</p>
Procedure for Direct Recruitment	15.	<p>Procedure of direct recruitment on the posts of Assistant Accountant -</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Application for being considered for selection shall be called by the Commission in the prescribed form, which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment. (2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission. (3) After the results of the written examination has been received and tabulated, with the consultation of the Commission fixed syllabus by the Government in mentioned subject of competitive examination, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories of candidates under regulation 6, recommend for appointment such number of candidates as on the result of the

		written examination. If two or more candidates obtained equal marks, than the senior candidate in age shall be placed higher on the list. The commission shall forwarded the list to the appointing authority
Procedure of Recruitment by Promotion	16.	<p>Procedure of recruitment by promotion on the post of Accountant-</p> <p>(1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, which comprises as follows :-</p> <p>(a) 'appointing authority' -- Chairman;</p> <p>(b) a senior officer of commission nominated by the appointing authority -- Member;</p> <p>(c) finance controller of commission nominated by the appointing authority -- Member;</p> <p>Provided that if in the such constituted selection committee, the concerning person of each of Schedule Caste/ Schedule Tribes and Other Backward Classes in not incorporate, than such Castes or Tribes and Classes, who have not representation in the Selection Committee, from any concerning officer, who is not less than the rank of Joint Secretary shall be nominated as member of selection committee.</p> <p>(2) The Appointing Authority, shall prepare a eligibility list according the Uttarakhand Promotion by Selection in Consultation with the Public Service Commission (Procedure) Regulations, 2003 as amended from time to time.</p> <p>Explanation— in sub-regulation (b) of these regulation -</p> <p>(a) the number of vacancies means the total number of vacancies whether substantive or temporary vacancies to be filled during the year of recruitment or existing vacancies in the time of commencement of the recruitment of years;</p> <p>(b) for all type of vacancies the only one eligibility list shall be</p>

		<p>prepare.</p> <p>(3) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates and place it before the selection committee along with there character roles and such other records, pertaining to them, as may be considered proper and shall intimate number of different type of vacancies.</p> <p>(4) The Selection Committee shall consider the candidate on the basis of there records refer to in sub-regulation (3), it may interview the candidates also.</p> <p>(5) The Selection Committee shall prepare a eligibility list in order of seniority of the selected candidates and shall forward to the appointing authority.</p>
		<p style="text-align: center;">PART-VI</p> <p style="text-align: center;"><u>Appointment, Probation, Confirmation and Seniority</u></p>
Appointment	17.	<p>(1) The appointing authority shall make the appointments by taking the name of candidates in the order, in which they stand in the list prepared under regulation 14, 15 or 16 as the case may be.</p> <p>(2) If more than one or more orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the name of the persons in order of seniority as determined in the selection or as determined, as the case may be or as it is stood in the cadre from which they are promoted.</p>
Probation	18.	<p>(1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.</p> <p>(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted;</p> <p style="text-align: center;">Provided that have in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in</p>

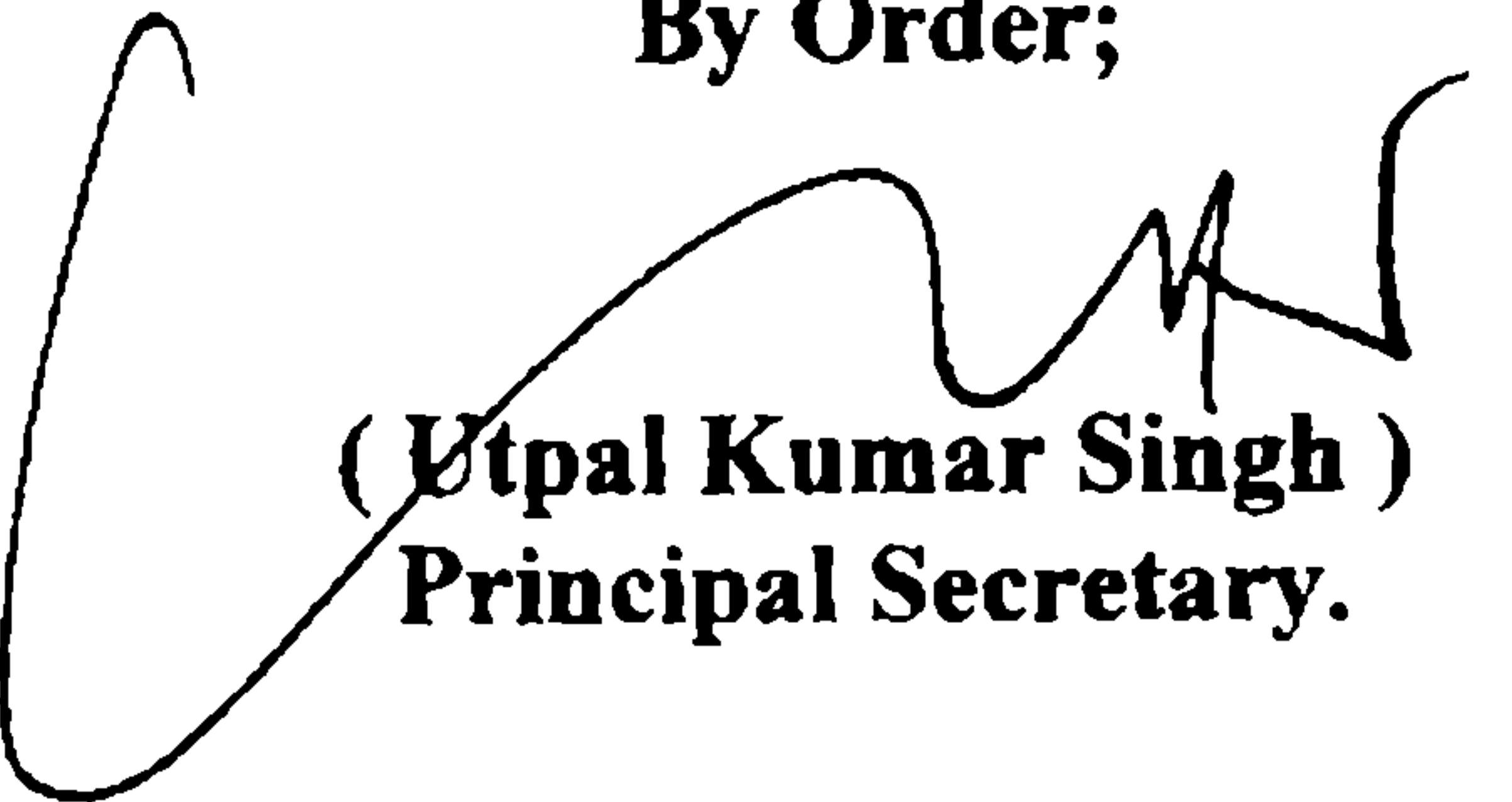
		<p>no circumstances beyond two years.</p> <p>(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extend period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his sustentative post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.</p> <p>(4) A probationer, who is reverted or whose services are dispensed with under sub-regulation (3) shall not be entitled to any compensation.</p> <p>(5) The Appointing Authority may allowed continuous service rendered in an officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken in to account for the purpose of computing the period of probation.</p>
Confirmation	19.	<p>(1) A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation of the extended period of probation, if -</p> <p>(a) he has passed the prescribed departmental examination; if any;</p> <p>(b) he has successfully undergone the prescribed training, if any;</p> <p>(c) his work and conduct is reported to be satisfactory;</p> <p>(d) his integrity is certified; and</p> <p>(e) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.</p>
Seniority	20.	<p>(1) The Seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttarkhand Government Servants Seniority Regulations, 2002, as amended from time to time;</p>

		<p>Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person substantively appointed, that date, will be deemed to be the date of order of substantive appointment and in other case, it will mean the date of issue of the order.</p> <p>(2) The Seniority <i>inter se</i> of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.</p>
		<p style="text-align: center;">Part - VII</p> <p style="text-align: center;"><u>Pay etc.</u></p>
Scale of Pay	21.	<p>(1) The Scale of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, whether in a sustentative or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.</p> <p>(2) The Scales of pay at the time of commencement of these regulations shall be, as indicated at Annexure "A".</p>
Pay during probation	22.	<p>(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rule to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in time scale when he has completed one year of satisfactory service has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed;</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.</p> <p>(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the reverent</p>

		<p>Fundamental Rules;</p> <p>Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment.</p> <p>(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant regulation, applicable generally to Government servants serving in connection with the affaire of the State.</p>
		<p style="text-align: center;">PART - VII</p> <p style="text-align: center;"><u>Other Provisions</u></p>
Canvassing	23.	No recommendation either written or oral other than those required under the regulations applicable to the post or service will be taken into consideration. Any criteria of attempt on the part of a candidate to enlist support directly for this candidature will disqualify him for appointment.
Regulation of other matters	24.	In regard to the matters not specially conveyed by these regulations or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the regulations, regulations and orders applicable generally to the Government servants serving in connection with affaire of the State.
Relaxation from the conditions of service	25.	Where the State Government is satisfied that the operation of any regulation regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the regulations applicable to the case, by order dispense with or relax the requirements of that regulation to such extent and subject to such condition, it may consider necessary for dealing with case in a just an equitable manner;

		<p>Provided that where a regulation has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the regulation are dispensed with or relaxed.</p>
Savings	26.	<p>Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidate belonging, to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other special categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with the order of the Government issued from time to time in this regard.</p>

By Order;



(Utpal Kumar Singh)
Principal Secretary.

Annexure 'A'

[Please see sub-regulation (2) of regulation 4 and sub-regulation (2) of regulation 21]

S. No.	Name of Post	Pay (Rs.)	Number of posts		Total
			Permanent	Temporary	
1	2	3	4	5	6
1	Assistant Accountant	5200-20200 Grade Pay- 2800	--	02	02
2	Accountant	9300-34800 Grade Pay- 4200	--	01	01